बढ़ती मुश्किलों के बीच इमरान की चुनौती

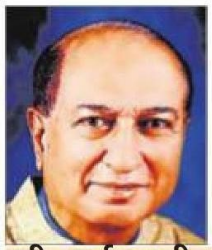

जी. पार्थसारथी

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व सऊदी अरब से मदद के प्रति आश्वस्त होकर पाकिस्तान की शाहबाज सरकार को आर्थिक मोर्चे पर फौरी राहत मिली है लेकिन उसके सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। महंगाई के चलते इमरान खान नीत विपक्षी पार्टी पीटीआई ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। अगले साल चुनाव हैं और आईएमएफ के कर्ज की शर्तों के तहत कड़ी नीतियों को जनता पर लागू करना होगा। वहीं भारत के साथ पाक का रवैया ठीक रहा तो संबंध बढ़ाये जा सकते हैं।

लग रहा है कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा अमीर परिवारों में एक से आए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ अपने बड़े भाई नवाज़ शरीफ़ के पदचिन्हों पर हैं, जो इन दिनों लंदन में आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला पाकिस्तान में चल रहा है। यह तथाकथित आर्थिक अपराध खासतौर से सऊदी अरब स्थित उनकी स्टील मिल को लेकर बताया गया है। यह दोष नवाज़ शरीफ पर 2018 में राष्ट्रीय चुनाव में हार के बाद लगा, जब इमरान खान ने बतौर प्रधानमंत्री उनकी जगह ली। इमरान खान की जीत के पीछे का एक तथ्य यह भी था कि उस वक्त वे पिछले कई सालों से सैन्य प्रतिष्ठान के पसंदीदा नेता थे। बता दें कि सऊदी अरब में स्टील मिल नवाज शरीफ को विरासत में मिली है। शरीफ़ खानदान काफी लंबे समय से सऊदी सुल्तानशाही का अंतरंग परिवार है।

रिवायती रूप से भी सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं, लेकिन इनको उस वक्त झटका लगा जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तुर्की और मलेशिया के नेतृत्व में बने नए इस्लामिक संगठन से जुड़ने का मन बनाया, जिसका मकसद इस्लामिक जगत को नया आयाम देना रहा है और इससे सऊदी अरब की सरदारी कमतर बनती है। लगता है इमरान खान को इस्लामिक जगत की अंदरूनी राजनीति के बारे में जानकारी कम है। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया की तिकड़ी बनने पर सऊदी अरब का खार खाना स्वाभाविक था और जिन पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति वह पाकिस्तान को घटी दरों और उधार पर करता आया है, उसमें अड़ंगा लगना ही था। ऐसे में पाकिस्तान को ऐसा कोई अन्य देश मिलना लगभग नामुमकिन था, जो दयनीय आर्थिक स्थिति में सऊदी अरब जितना मददगार होता।

जब भी पाकिस्तान में शरीफ खानदान की सरकार आई तो प्रधानमंत्री सबसे पहले सऊदी अरब की यात्रा पर गए और यही शाहबाज़ शरीफ ने भी किया, ताकि सऊदी अरब के राजपरिवार से संबंध फिर से मधुर बन सकें। उनकी यात्रा के बाद संकेत मिले कि सऊदी अरब पाकिस्तान को 8 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देगा। विगत में पाकिस्तान को मिलने वाले तेल की आपूर्ति उदार शर्तों और आसान ऋण अदायगी के रूप में होती रही है।

नकदी का टोटा भुगत रहे पाकिस्तान के लिए यह खबर अच्छी है। सऊदी अरब के बाद शाहबाज़ शरीफ यूएई पहुंचे, जो अप्रवासी पाकिस्तानी कामगारों के लिए रोजगार का सबसे प्रमुख स्रोत है। किंतु पाकिस्तान की आर्थिक मुसीबतें निरंतर बनी हुई हैं और विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है। कोई हैरानी नहीं कि सेना ने संसद में इमरान खान को पटखनी दिलवाने में मदद की और शाहबाज़ शरीफ़ के नेतृत्व में नई सरकार बनवा दी।

परंतु पिछला हफ्ता शाहबाज़ सरकार के लिए मुसीबतज़दा रहा है। लगातार बढ़ते दामों ने राष्ट्रव्यापी नाराज़गी को भड़काया है। इसके अलावा, इमरान खान की अगुवाई में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनों ने गंभीर राजनीतिक अशांति मचा दी है। मामला उस वक्त संजीदा हुआ जब इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने 17 जुलाई को हुए उपचुनाव में 20 में से 15 सीटों पर कब्जा कर एक तरफा विजय हासिल कर ली। इस घटना को इमरान खान की सेनाध्यक्ष बाजवा पर निजी जीत की तरह भी देखा जा रहा है, जो जाहिर तौर पर शरीफ़ सरकार का साथ दे रहे हैं। यह जीत शाहबाज शरीफ़ के बेटे के लिए भी निजी पराजय बनी और उन्हें पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और अपनी जगह मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता चौधरी परवेज़ इलाही को देनी पड़ी।

सेनाध्यक्ष बाजवा की इमरान के प्रति नापसंदगी के बावजूद सेना का बड़ा तबका उनके द्वारा अमेरिका के प्रति दिखाई दृढ़ता से अंदर-ही-अंदर प्रशंसक बन चुका है। हालांकि असलियत से वाकिफ लोग समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद के बिना पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था वित्तीय रूप से ढह जाएगी। परंतु इस किस्म की मदद अमेरिका की सहायता के बिना संभव नहीं है और अमेरिका परस्त जनरल बाजवा यही इनायत पाने की कोशिश में हैं। भरोसेमंद अमेरिकी मदद के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सहायता तब देना माना जब जनरल बाजवा ने एक अभूतपूर्व कदम में अमेरिकी उप-विदेश मंत्री वेंडी शर्मन को स्वयं टेलीफोन करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद पाने में समर्थन और सहायता मांगी। लेकिन आईएमएफ और सऊदी अरब से मिली आर्थिक मदद भी पाकिस्तान को वित्तीय रूप से उबारने में नाकाफी है। इसी बीच मुल्क के अंदर जारी राजनीतिक उठापटक में इमरान खान के विरोधी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन पर पर भी आर्थिक और अन्य अपराधों में केस दर्ज हों।

जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी मंडल ने पाकिस्तान को उबारने के लिए 39 महीनों की अवधि वाली 6 बिलियन डॉलर की सहायता देने को मंजूरी दी है वहीं आने वाले समय में सामाजिक खर्च में कटौती करना और ऋण की अन्य शर्तों को पूरा करना मौजूदा सरकार को राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय बना डालेगा। इन उपायों में, तनख्वाहें और पेंशनों में अतिरिक्त वृद्धि की मौजूदा योजना में बड़े बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। पेट्रोलियम और बड़े पैमाने पर खपत वाली अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बहुत इजाफा होगा। उच्च आय वर्ग के परिवारों पर टैक्स की मात्रा बढ़ेगी। अपना ऐशो-आराम बरकरार रखने वाली सेना इन कदमों को किस रूप में लेगी, यह देखना बाकी है। हालांकि सऊदी अरब, यूएई, कतर और चीन ने पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 4 बिलियन डॉलर की जमानत लेने का संकल्प लिया है, किंतु इस काम में पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में तकलीफदेह ढांचागत परिवर्तन करना शामिल है।

पहले से ही बहुतेरी अंदरूनी चुनौतियां झेल रहे पाकिस्तान के लिए आने वाला समय उथल-पुथल भरा हो सकता है, अगले साल 2023 में आम चुनाव तय हैं। वहीं आने वाले महीनों में, जनरल बाजवा बतौर सेनाध्यक्ष अपनी पारी के अंतिम पड़ाव में होंगे, जब 29 नवम्बर को उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, इस अवधि में घटनाचक्र लगातार घूमता रहेगा। यह तय है कि सरकार को जनता से जारी समर्थन से उत्साहित हुए इमरान खान से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच पाकिस्तान जिस रूप में मदद पाना चाहेगा उस पर बाइडेन प्रशासन का रवैया कंजूसी भरा होगा।

सऊदी अरब ने शाहबाज़ शरीफ की अगुवाई वाली सरकार को मदद देने में कदम बढ़ाया है। इसी बीच चीन अपनी ओर से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के लिए अपनी मदद जारी रखे हुए है, उसने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए काफी सोच-विचार के बाद आगे बढ़ना चुना है। हालात अनुकूल हैं तो जाहिर है जनरल बाजवा खुद की पसंद का अपना उत्तराधिकारी बनाना प्रस्तावित करेंगे। देखना यह है कि उनका उत्तराधिकारी और शाहबाज़ सरकार इमरान की बढ़ती लोकप्रियता से किस तरह निबटेंगे। भारत के साथ संबंध आगे भी जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को आईएसआई की परोक्ष-अपरोक्ष मदद से जुड़े रहेंगे। हालांकि पाकिस्तान जानता है कि भारत को सीमा पार जाकर आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने में हिचक नहीं होगी। तथापि, दोनों देशों के बीच राजनयिक, और यहां तक कि राजनीतिक स्तर का राब्ता जारी रखना चाहिए। सावधानी पूर्वक तैयारियों के बाद, नागरिक-का-नागरिक से संपर्क माध्यम खोला जाना चाहिए।

लेखक पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं।